The State DPEP Society had an unspent balance of Rs. 26.58 crores as on 1.4.98. An additional request for funds received from the Government of Andhra Pradesh in regard to the Education Component of Andhra Pradesh Economic Restructuring Project is under consideration in consultation with the Planning Commission for additional allocation of resources.

Shortage of Staff of NCW

2906. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state.

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item which appeared in the Sunday Times of India (New Delhi), dated the 7th March, 1999 under the caption "NCW faces staff crunch on women's day" wherein it has been stated that the National Commission for Women (NCW) is facing acute shortage of staff;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the measures Government propose to take to provide adequate staff to the Commission?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND THE DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SUSHREE UMA BHARTI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) 28 posts were sanctioned at the time of setting up of National Commission for Women (NCW) on 31st January, 1992, 9 Additional posts, as recommended by an Internal Work Study, were sanctioned on 28.5.1997. To consider the requirement of additional staff proposed by the National Commission for Women, a study has been conducted through the Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance. The Report is awaited.

देश में प्राथमिक विद्यालयों हेतु नयी योजना

2907. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा देश में, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक विद्यालय संचालन करने के लिए एक नयी योजना चालू करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की योजना है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन से राज्यों को चुना गया है और प्रत्येक राज्य में कितने-कितने विद्यालय शुरू किए जाने हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) वर्ष 1999-2000 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा गारंटी योजना कार्यान्वित करना प्रस्तावित किया है। इसका लक्ष्य प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में जहां पर 1 कि०मी० क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है, वहां एक प्रारंभिक स्कूल की व्यवस्था की जाएगी। प्रारंभ में, स्थानीय समुदाय, परिसर स्थान की व्यवस्था करेंगे तथा अंशकालिक अध्यापक के रूप में एक स्थानीय व्यक्ति का चयन करेंगे। अध्यापन सामग्री और अन्य सहायता केन्द्रीय और राज्य सरकारें प्रदान करेंगी जबकि ग्राम पंचायत स्कूल चलाने के लिए कम से कम दो वर्ष तक स्थानीय समुदाय से नकद और सामान के रूप में धन एकत्र करेंगी। दो वर्ष सफलतापूर्वक कार्य करने के पश्चात् स्कूल को स्थायी आधार पर स्तरोन्नयन कर दिया जाएगा। नौवीं योजना के अगले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के कम से कम 1.8 लाख स्कूल कार्य करना आरंभ कर देंगे।

(घ) योजना के विस्तृत ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।